ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL**04292**
RNI REG. NO. UPBIL/**2014/66218** **PP. No.- 119-122**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- II, Issues-40, YEAR- April-June 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत–नेपाल के बीच राजनीतिक संबंध का विश्लेषण (2014–25)

सचिन कुमार पाण्डेय

शोध अध्येता– राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (मध्य प्रदेश) भारत

Received-02.04.2026, Revised-07.04.2026, Accepted-12.05.2026, E-mail:isachinp27@gmail.com

सारांशः भारत–नेपाल के बीच सदियों से घनिष्ट सामाजिक व सांस्कृतिक संबंध विद्यमान है। इन संबंधों को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए राजनीतिक संबंधों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के समझौतों व ज्ञापनों के द्वारा मजबूत करने पर बल दिया जाता रहा है। इस शोध पत्र में दोनों राष्ट्रों के राजनेताओं के समय–समय पर एक–दूसरे के बीच यात्राओं के माध्यम से सामाजिक व सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने के साथ आर्थिक क्षेत्रों में भी शक्तिसंपन्न व सशक्त बनने के लिए विभिन्न प्रकार के समझौतों ज्ञापित हुए है की भी चर्चा की गई है। साथ ही दोनों राष्ट्रों के बीच उतार–चढ़ाव को रेखांकित करते हुए भारत के तरफ से नेपाल को दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सहयोग की भी पड़ताल की गई है।

कुंजीभूत शब्द– आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धर्म समाज, नैतिकता मूल्यों, सामाजिक नियंत्रण, अलौकिक शक्ति, जीवन।

भारत व नेपाल के बीच संबंध ऐतिहासिक काल से ही घनिष्ट रहे है यह संबंध केवल सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा धार्मिक जीवन तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच समय–समय पर घनिष्ट सम्बंध स्थापित हुए। आधुनिक युग में भारत एवं नेपाल के बीच राजनीतिक संबंधों का शुभारंभ 1816 की सुगौली संधि से हुआ। भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारत–नेपाल संबंधों में एक नये युग का आरंभ हुआ। समय के साथ–साथ संबंधों में नेपाल व भारत में राजनीतिक परिवर्तन व घटनाक्रम के कारण उतार–चढाव भी आते रहे। लेकिन नेपाल की भू–राजनीतिक स्थिति व आंतरिक कलह के कारण राजतन्त्र के विरुद्ध आन्दोलन करके समय–समय पर लोकतंत्र को लेकर मांग उठती रही जिस कारण नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था काफी उठा–पुथल भरी रही। जिसका प्रभाव भारत–नेपाल के संबंधो पर पड़ना स्वभाविक था। लेकिन संबंधों को नई आयाम तक पहुँचाने में राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता। भारत की समझदारी भरी राजनीति नेतृत्वकर्ताओं ने सूझ–बुझ कूटनीति व रणनीति के माध्यम से नेपाल की उथल–पुथल भरी नेपाल की अस्थिर राजनीतिक नेतृत्वकर्ताओं के साथ तालमेल स्थापित करके संबधों को बरक़रार रखकर घनिष्ट करने पर बल दिया। जिसमें नेपाल की राजनीतिक नेतृत्व का भी अहम योगदान रहा। हालाँकि भारत के विरोध में नेपाली जनमानस के साथ राजशाही व्यवस्था व राजनीतिक पार्टियों में आवाजें उठती रही जिसमें नेपाल नरेश व विशेषकर पहाडी लोगों में उनके अपने–अपने तर्क व मत थे।

भारत में वर्ष 2014 के आम चुनाव के फलस्वरूप यु.पी.ए. सरकार के बाद एन. डी.ए. के नेतृत्व वाली सरकार का गठन हुआ। जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। प्रधानमंत्री पद पर सत्तारूढ़ होते ही मोदी ने सर्वप्रथम पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंध को बेहतर करने का निश्चय किया। साथ ही शपथ समारोह में सार्क के सभी राष्ट्रों को निमंत्रण भेजा। जबकि यूपीए सरकार की विचारधारा को सर्व समावेशी बताई जा रही थी लेकिन उन्होंने कभी इस बारे में चिंतन–मनन की जरूरत महसुस नहीं की कि पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत के संबंध क्यों बिगड़ते जा रहे है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ में ही महसुस करके पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहे। "प्रथम पड़ोस नीति" के तहत नेपाल को सबसे आगे रखा। प्रधानमंत्री मोदी की नेपाल यात्रा से पूर्व तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नेपाल के तत्कालीन विदेश मंत्री महेंद्र नाथ पांडे के निमंत्रण पर 25–27 जुलाई 2014 को तीन दिवसीय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने भारत–नेपाल संबंधों में पूर्वाग्रह को दूर करने की कोशिश की। भारत–नेपाल संबंधों में तनाव का महत्वपूर्ण कारण 1950 की शांति एवं मैत्री संधि है। इस संधि को नेपाल के तरफ से असमान बताकर भारत के संदर्भ में लाभकारी बताई जाती है। भारत ने नेपाल के साथ 76 साल पुरानी इस संधि की समीक्षा करने और समयानुरूप ढालने की सहमति देकर नेपाल के साथ रिश्तों में आए संदेह को दूर किया है। साथ ही भारत ने नेपाल के रास्ते आने वाली चीनी उत्पादों को नेपाल का उत्पादन मान कर इसे 'कर–मुक्त निर्यात करने की अहम छूट दी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज एवं विदेश मंत्री महेंद्र बहादुर पांडे ने साझा आयोग की 23 साल बाद हुई तीसरी बैठक के दौरान यह निर्णय लेकर नेपाल की व्यापार असंतुलन की शिकायत को दूर किया। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने व्यक्तव्य में कहा कि, 'मैं अपनी नेपाल यात्रा से बहुत संतुष्ट हुँ और यह उम्मीद से ज्यादा सफल रही। नेपाल–भारत संबंध मजबूत होंगे और हमने इसके लिए एक पूरा प्लान तैयार किया है।'' इसके उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय यात्रा पर 3–4 अगस्त 2014 को नेपाल गए। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा 17 सालों बाद हुई थी। इससे पूर्व 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्द्र कुमार गुजराल ने नेपाल की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा के दौरान नेपाल को 1 अरब डॉलर का रियायती ऋण देने की घोषणा की एवं नेपाली संविधान सभा को भी संबोधित किया। संविधान सभा में हिन्दी में भाषण देते हुए नेपाल को अपनी विदेश नीति में उच्च प्राथमिकता पर बताया। उन्होंने कहा, 'नेपाल के आंतरिक मामलों में दखल देना हमारा काम नहीं है, बल्कि आपने जो रास्ता चुना है, हम उसमें आपकी मदद करना चाहते है। मैं नेपाल को हिट करना चाहता हुँ। मेरी डिक्शनरी के मुताबिक, हिट का मतलब है, H: हाइवेज, I: आई–वेज T: ट्रांसवेज। इसके अलावा मोदी ने 1950 की शांति एवं मैत्री संधि के आशंकाओं पर कहा कि अगर नेपाल कोई संशोधन चाहता है तो स्वागत है। एक साझा बयान में कहा गया कि नई संशोधित संधि मौजूदा समय के अनुरूप तैयार की जाएगी। इसका इरादा आज की वास्तविकताओं के अनुरूप दोनों देशों के बहुयामी रिश्तों को ढालने का होगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने पशुपतिनाथ मंदिर के भी दर्शन किए। इस प्रकार नेपाल दौरा नेपाली संसद को संबोधन से लेकर पशुपतिनाथ के दर्शन तक एक–एक कदम नपा–तुला एवं संतुलित रहा। इसके बाद नेपाल के तत्कालीन विदेश मंत्री महेंद्र बहादुर पांडे ने भारत की तीन दिवसीय यात्रा 19–21 अक्टूबर 2014 के दौरान की। इसके बाद 25–27 नवम्बर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के काठमांडू में आयोजित सार्क शिखर सम्मेलन बैठक में भाग लेने के लिए गए। इस दौरान भारत–नेपाल के बीच द्विपक्षीय समझौते भी हुए। जिसमें यात्री यातायात के लिए भारत–नेपाल द्विपक्षीय मोटर वाहन करार में दोनों देशों के बीच सहमत हुए मार्गों, यात्राओं और समय सारणी के अनुसार नियमित बस सेवाओं की परिकल्पना की गई। यह भारत–नेपाल सीमा पार निजी और गैर–नियमित वाहनो के आवागमन की प्रक्रिया को सरल बनाता है। जिससे लोगों के बीच

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

संपर्क बढ़ाने के साथ–साथ पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने काठमांडू दिल्ली यात्री बस सेवा, पशुपतिनाथ एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नेपाल को 1 अरब यूएस डॉलर का ऋण विद्युत, सिचाई और ढ़ाचागत विकास परियोजनाओं के लिए प्रदान की। इसके अलावा राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, पनौती के संबंध में समझौता ज्ञापन एवं आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और स्वास्थ्य जनसंख्या, नेपाल सरकार के बीच सहयोग के लिए परंपरागत चिकित्सा प्रणाली सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन हुआ। भारत एवं नेपाल के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन क्षेत्र से संबंधित सूचना और डाटा को आदान–प्रदान पर्यटन हितधारकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना,पर्यटन और अतिरिक्त उद्योग के हितधारकों के बीच सहयोग और प्रत्यक्ष संप्रेक्षण को बढ़ावा देना एवं एक संयुक्त कार्य समूह का गठन करने को लेकर समझौता हुआ। भारत–नेपाल के बीच जनकपुर–अयोध्या, लुम्बनी–बोधगया और काठमांडू–वाराणसी को इनके गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों के कारण सिस्टर–सिटीज के रूप में जोड़े जाने का प्रस्ताव हुआ। इसके अलावा युवा मामलों के लिए सहयोग के संबंध में, नेपाल में भारतीय मुद्रा के 500 और 1000 नोटों के चलन को लेकर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर के बोधिवृक्ष की सैंपलिंग लाकर लूम्बनी के माया मंदिर परिसर में अशोक स्तंभ के पास लगाए जाने के लिए भेंट भी की। इसके बाद नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत की सात दिवसीय यात्रा 14–20 जुलाई 2015 पर आए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके अलावा नेपाल के संविधान से जुड़े मुद्दे को लेकर भी बात किया। इस यात्रा बाद ही पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा 29 जुलाई से 2 अगस्त 2015 को भारत की यात्रा पर आए तथा विदेश मंत्री कमल थापा भी 17–19 अक्टूबर 2015 को भारत आए। नेपाल के तरफ से इन यात्राओं के बाद भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज नेपाल की यात्रा 9 फरवरी 2016 को की। इसके बाद नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली 19–24 फरवरी 2016 को छः दिवसीय यात्रा पर भारत आए। अक्टूबर 2015 में पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री ओली की यह पहली यात्रा थी। इस दौरान राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से भी मुलाकात के बाद भारत–नेपाल के बीच द्विपक्षीय समझौते भी हुई। इनमें शामिल थे– भूकंप के पश्चात पुनर्निर्माण सहायता के लिए भारत सरकार के सहायता पैकेज के 250 मिलियन अमरीकी डॉलर के अनुदान घटक पर एमओयू, नेपाल के तराई क्षेत्र में सड़क अवसंरचना के सुदृढीकरण पर एमओयू, नेपाल संगीत एवं नाटक अकादमी तथा संगीत नाटक अकादमी के बीच एमओयू, पारगमन मार्गों पर पत्र विनिमय, रेलवे परिवहन पत्र विनिमय, मुजफ्फरपुर, ढलकेबार पारेषण लाइन का उद्घाटन एवं द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा हेतु प्रख्यात व्यक्ति समूह का गठन शामिल था। प्रधानमंत्री ओली की यात्रा के बाद भारत–नेपाल संबंधों को सुदृढ़ करने हेतु 16–17 मार्च 2016 को भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नेपाल की यात्रा की। इसके बाद 10–12 जून 2016 को नेपाल के उप–प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने भारत की यात्रा की।

भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निमंत्रण पर नेपाल के तत्कालीन विदेश मंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत 11–13 सितंबर 2016 को भारत यात्रा पर आए। इस दौरान व्यापार और निवेश प्रतिरक्षा और सुरक्षा, आर्थिक और विकास भागीदारी, बुनियादी ढांचे के विकास,ऊर्जा और जल संसाधन जैसे विविध क्षेत्रों में सदियों पुराने, घनिष्ट और मैत्रीपूर्ण संबंधों को आगे तथा मजबूत बनाने एवं वस्तुओं और सेवाओं, लोगों एवं विचारों के आदान–प्रदान की सुविधा को बढ़ाने के प्रति प्रतिबद्धता की गई। इस यात्रा के बाद 15–18 सितंबर 2016 को चार दिवसीय यात्रा पर नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और उनकी पत्नी श्री मती सीता दहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राजकीय यात्रा पर आए। इस दौरान आपसी हीत एवं चिंता के मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही दोनों देशों के बीच विविध क्षेत्रों में सदियों पुराने, घनिष्ट और मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने पर बल दिया। इसके अगले माह पुनः नेपाल के तत्कालीन विदेश मंत्री ने भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर 26–28 अक्टूबर 2016 को आए। नेपाल के तरफ से इन यात्राओं के बाद भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने 2–4 नवंबर 2016 में नेपाल की तीन दिवसीय यात्रा की। 18 वर्षों के उपरांत किसी भारतीय राष्ट्रपति ने नेपाल की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुखर्जी अपने समकक्ष नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारी से मिले और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल और अन्य नेताओं के साथ आपसी हितों के कई मुद्दों पर बैठक की। इसके अलावा जनकपुर एवं पोखरा का भी दौरा किया।

वर्ष 2017 में 16–18 जनवरी को नेपाल के तत्कालीन विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए। इसके बाद नेपाल के प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी 17 अप्रैल से 21अप्रैल तक चार दिवसीय यात्रा पर भारत आई। इस आधिकारिक यात्रा के दौरान राष्ट्रपति भण्डारी उड़ीसा और गुजरात भी गई। इस दौरान भारत–नेपाल संबंध के सदियों पुराने द्विपक्षीय संबंध को मजबूती आने की उम्मीद जताई। नेपाल के नए संविधान पर उपजे विवाद और मधेसीयों की समस्या के संदर्भ में भी बात हुई। गौरतलब है कि नेपाल के नए संविधान पर भारत के विरोध के कारण दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव चरम पर पहुँच गया था। इस मामले में नेपाल ने पहली बार भारत पर आर्थिक नाकेबंदी का आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा तथा डॉ. आरजू देउबा 23–27 अगस्त 2017 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। साथ में नेपाल के वित, विदेश संस्कृति व पर्यटन एवं वाणिज्य मंत्री सहित अन्य वरिष्ट अधिकारी शामिल थे। इस दौरान भारत–नेपाल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन हुआ। 2018 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 1–2 फरवरी को काठमांडू यात्रा पर गई। नवंबर–दिसंबर 2017 में नेपाल में संपन्न संसदीय और पहली बार हुए प्रांतीय विधानसभा के चुनाव के बाद विदेश मंत्री नेपाल जाने वाली भारत की पहली उच्चस्तरीय अतिथि थी। विदेश मंत्री ने सीपीएन–यूएमएल के अध्यक्ष के. पी. शर्मा ओली, सीपीएन–एमसी के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड, एसएसएफ–एन के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव और प्रेसिडियम के समन्वयक महंत ठाकुर तथा आरजेपी–एन के अन्य नेताओ के साथ बैठके की और हाल में हुए चुनावों में उनकी जीत पर उन्हें बधाई दी। यह बताई कि चुनाव नेपाल के लोकतान्त्रिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश मंत्री ने नेपाल के राजनीतिक नेताओं को अवगत कराया कि भारत सरकार पारस्परिक हितों के लिए द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुँचने के लिए लोकतान्त्रिक ढंग से चुनी गई नेपाल सरकार के साथ काम करने और नेपाल सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार, त्वरित आर्थिक विकास एवं विकास के प्रयासों में उसका समर्थन के लिए उत्सुक हैं। नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11–12 मई 2018 को नेपाल की राजकीय यात्रा पर गए। नेपाल में नई सरकार के गठन के बाद से यह नेपाल के लिए पहली उच्चस्तरीय यात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी नेपाल यात्रा थी। दोनों प्रधानमंत्री ओली एवं मोदी ने 2018 में अपने द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन को चिन्हित करते हुए 11 मई 2018 को प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता आयोजित की, जो अत्यंत गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। इस वार्ता ने दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती और समझ को दर्शाया। इस दौरान कृषि,रेलवे संबंधों को

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- II, Issues-40, YEAR- April-June 2026

अन्तर्देशीय जलमार्ग विकास में द्विपक्षीय पहल के प्रभावी कार्यान्यवन पर सहमति व्यक्त की। साथ ही भारत व नेपाल के बीच व्यापारिक और आर्थिक महत्व को रेखांकित किया। भारत के साथ व्यापार घाटे पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि इस घाटे को दूर करने के उपाय करने की जरूरत है। इस संदर्भ में दोनों प्रधानमंत्रीयों ने व्यापारिक द्विपक्षीय संधि की व्यापक समीक्षा करने और संधि में संशोधन पर विचार करने और अनाधिकृत व्यापार को नियंत्रित करने के लिए व्यापार व पारगमन और सहयोग पर हाल ही में आयोजित अंतर सरकारी समिति की बैठक के परिणाम का स्वागत किया और भारतीय बाजार में नेपाल की पहुँच को आगे बढ़ाने, समग्र द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और नेपाल के पारगमन व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए ट्रांजिट और संबंधित समझौतों को संशोधित करने पर विचार करने पर सहमति बनी। इसके आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और लोगों के आवागमन को बढ़ावा देने में संपर्कों की उत्प्रेरक भूमिका को रेखांकित किया। वे वायु, भूमि और पानी से आर्थिक और भौतिक संपर्क को बढ़ाने के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए। लोगों की आपसी जीवंत संपर्कों और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को पहचानते हुए दोनों प्रधानमंत्रीयों ने संबंधित अधिकारीयों को संबंधित तकनीकी टीमों द्वारा नेपाल के अतिरिक्त हवाई प्रवेश मार्गों पर प्रारंभिक तकनीकी चर्चा सहित नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए निर्देश रेखांकित दिया। इसके अलावा नदी प्रशिक्षण कार्यों, प्लावन और बाढ़ प्रबंधन, सिचाई और चल रही द्विपक्षीय परियोजनाओ के क्रियान्यवन को गति बढ़ाने के क्षेत्र में पारस्परिक लाभ के लिए जल संसाधनों के सहयोग को आगे बढ़ाने के महत्त्व को दोहराया। संयुक्त टीम के सहारे प्लावन और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों की यात्रा करेगी। और टिकाऊ समाधान के लिए उचित उपायों पर विचार करेगी। संयुक्त रूप से नेपाल में 900 मेगावाट अरुण जल विद्युत परियोजना की नीव रखी गयी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जनकपुर और मुक्तिनाथ का भी दौरा किया और काठमांडू व जनकपुर में नागरिक स्वागत समारोह में भाग लिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ओली व मोदी ने दोनों राष्ट्रों और लोगों के बीच घनिष्ट धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए नेपाल–भारत रामायण सर्किट को जनक नंदनी सीता के जनमस्थली जनकपुर,अयोध्या और महाकाव्य रामायण से जुड़े अन्य स्थानो से जोडेने के कार्य का शुभारंभ किया। जनकपुर व अयोध्या के बीच सीधी बस सेवा का भी उद्घाटन हुआ। इस प्रकार मोदी की तीसरी ऐतिहासिक यात्रा ने दोनों देशों के बीच पुरानी मैत्री संबंधों को और मजबूत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को भारत आने का निमंत्रण भी दिया।

इसके बाद नेपाल के काठमांडू में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन 30–31 अगस्त 2018 नेपाल के काठमांडू में आयोजित सम्मेलन में भाग लेने के लिए नेपाल का दौरा किया। यह प्रधानमंत्री मोदी का चौथा नेपाल दौरा था। बिम्सटेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे नेपाल के प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली से मिले और उन्हे बधाई दी। इस दौरान भारत–नेपाल के बीच द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन भी हुआ। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री ओली एवं मोदी ने संयुक्त रूप से 31अगस्त 2018 को नेपाल के काठमांडू तिलगंगा में पशुपतिनाथ धर्मशाला का उद्घाटन किया। इस धर्मशाला में 400 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है और यह धर्मशाला भारत–नेपाल मैत्री का प्रतीक है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने नेपाल की पहली यात्रा में इस धर्मशाला के निर्माण की घोषणा किया था। भारत ने इसके निर्माण में 25 करोड़ रुपये की मदद की थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी किया।

इसके बाद नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने भी 10–11 जनवरी, 2019 को भारत के नई दिल्ली में हो रहे रायसीना संवाद के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए भारत यात्रा पर आए। इस दौरान दोनों विदेश मंत्रीयों सुषमा स्वराज व ग्यावली के बीच विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों के हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की गई। विदेश मंत्री ग्यावली ने संयुक्त आयोग की अगली बैठक की सह–अध्यक्षता के लिए विदेश मंत्री को आने का निमंत्रण दिया। वर्ष 2019 में 21–22 अगस्त को भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों की समग्र स्थिति की समीक्षा करने के उद्देश्य से 'नेपाल–भारत संयुक्त आयोग' की पाँचवी बैठक में हिस्सा लेने के लिए नेपाल गए। इसकी शुरुआत भारत–नेपाल संबंध को बेहतर बनाने हेतु हुई थी,इस बैठक शुरुआत 1987 में प्रारंभ हुई थी।

इसके बाद वर्ष 2021 में 14–16 जनवरी को नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ज्ञवाली भारत की आधिकारिक यात्रा पर नेपाल–भारत संयुक्त आयोग की छठी बैठक में भाग लेने के लिए आए। जिसकी अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्वाली द्वारा की गई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच बहुमुखी सहयोग के सभी आयामों की समीक्षा और करीबी एवं मैत्रीपूर्ण संबंधो को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई। बैठक में दोनों नेताओं के बीच संपर्क, अर्थव्यवस्था, कारोबार, ऊर्जा, तेल एवं गैस, जल संसाधन, राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़े मसलों, सीमा प्रबन्ध, पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा और क्षमता निर्माण समेत सहयोग के अनेक पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। इस क्षेत्र में कोविड़–19 महामारी का मुकाबला करने में दोनों देशों के बीच घनिष्ट सहयोग की सरहना की गई। नेपाल नें कोविशील्ड और कोवैक्सीन उत्पाद करने में सफलता पाने पर भारत को बधाई दी और नेपाल को जल्द ही वैक्सीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इसके अलावा मोतीहारी–अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन की सफलता को देखते हुए दोनों पक्षों ने इस पाइपलाइन को चितवन तक विस्तार करने और नेपाल में पूर्व की ओर सिलीगुड़ी झापा को जोड़ने वाली एक नई पाइपलाइन की स्थापना पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत–नेपाल के बीच जयनगर–कुरथा भाया जनकपुर तक ले जाने वाली पहली पैसेंजर रेलवे लाइन का काम पूरा होने का स्वागत किया और ट्रेन सेवाओं के संचालन हेतु परिचालन प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिए जाने की चर्चा की। इस दौरान संभावित रक्सौल से काठमांडू तक के ब्रांडगेज रेल लाइन समेत अन्य क्रॉस–बॉर्डर रेल कॉनेक्टविटी परियोजनाओं पर भी चर्चा की। संयुक्त आयोग ने दोनों देशों के नागरिकों, माल की सीमा पार आवाजाही को सुविधाजनक बनाने की आवश्कता पर बल दिया। इस बात पर चर्चा हुई कि हाल में बीरगंज और विराटनगर में खोले गए एकीकृत चेक पोस्टों से दोनों देशों के नागरिकों के निर्बाध आवागमन और व्यापार में मदद मिली है। दोनों मंत्रीयों ने नेपालगंज में तीसरे आईसीपी का निर्माण कार्य शुरू होने का स्वागत किया। भारत ने बताया कि भैरवा में नए आईसीपी का निर्माण जल्द ही शुरू हो जाएगा। दोनों पक्षों के बीच प्रस्तावित पंचेश्वर बहु–उद्देशीय परियोजना समेत संयुक्त जल विद्यूत परियोजना में तेजी लाने पर भी चर्चा हुई। जिससे दोनों देशों के नागरिकों को लाभ होगा। भारत ने बैठक में बताया कि वह नेपाल में पशुपतिनाथ रिवेरफ़्रंट डेवलपमेंट और पाटन दरबार में भंडारवाल गार्डन रेस्टोरेशन नामक दो और अनुदान सहायता के साथ सांस्कृतिक विरासत परियोजनाओं को शुरू करेगा। दोनों पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय और उप–क्षेत्रीय सहयोग पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। नेपाल ने संयुक्त सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने किसी उपयुक्त समय पर नेपाल में संयुत आयोग की अगली बैठक आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की।

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- II, Issues-40, YEAR- April-June 2026

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी डा. आरजू देउबा 1–3 अप्रैल 2022 को भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए। जुलाई, 2021 में पदभार ग्रहण करने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा की यह पहली विदेश यात्रा थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ व्यापक द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी प्रधानमंत्री देउबा से मिले। इन आधिकारिक कार्यक्रमों के अलावा प्रधानमंत्री देउबा ने वाराणसी का भी दौरा किया। द्विपक्षीय मुद्दों के अंतर्गत दोनों प्रधानमंत्रीयों ने विद्युत क्षेत्र में सकारात्मक विकास को नोट किया एवं बिजली क्षेत्र में पारस्परिक रूप से लाभप्रद द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार और मजबूत करने के लिए अभूतपूर्ण अवसर को रेखांकित किया गया।

नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर बुद्ध पूर्णिया के अवसर पर 16 मई 2022 को लूम्बनी नेपाल की आधिकारिक यात्रा की। प्रधानमंत्री के रूप में यह मोदी की पाँचवी और लूम्बनी की पहली यात्रा थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मायादेवी मंदिर का दौरा किया, जिसके भीतर बुद्ध का जन्म स्थान स्थित है। इसके ऐतिहासिक अशोक स्तंभ का दर्शन करके बोधि वृक्ष को जल से सींचा, जिसे नेपाल की पहली यात्रा अगस्त 2014 के दौरान उपहार स्वरूप लाए थे। इसके बाद देउबा के साथ लूम्बनी में नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (आईबीसी) के भू–खंड पर भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र के निर्माण के लिए आयोजित 'शिलान्यास' समारोह में भाग लिया। साथ ही लूम्बनी और कुशीनगर के बीच सिस्टर सिटी के संबंध स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए। दोनों देशों के लोगों को करीब लाने के लिए शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक आदान–प्रदान को बढ़ाने पर सहमति बनी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौतों के अंतर्गत भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद (आईसीआर) और लुम्बनी बौद्ध विश्वविद्यालय के बीच अंबेडकर अध्ययन पीठ के संबंध में समझौता ज्ञापन के अलावा भारतीय सांस्कृतिक परिषद (आईसीसीआर) और त्रिभुवन विश्वविद्यालय के सीएनएएस के बीच आईसीसीआर चेयर आफ इंडियन स्टडीज की स्थापना के संबंध में समझौता, भारतीय सांस्कृतिक परिषद (आईसीसीआर)और काठमांडू विश्वविद्यालय के बीच आईसीसीआर चेयर ऑफ इंडियन स्टडीज की स्थापना में समझौता, नेपाल के काठमांडू विश्वविद्यालय और भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान मद्रास की बीच सहयोगात्मक समझौता, नेपाल के काठमांडू विश्वविद्यालय और भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान के बीच स्नाकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के लिए समझौता पत्र एवं अरुण 4 परियोजना के विकास और कार्यान्यवन के लिया एसजेवीएन लिमिटेड और नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) के बीच समझौता ज्ञापन हुआ।

इसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने 31 मई –3 जून 2023 तक चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत आए। प्रधानमंत्री मोदी और नेपाली प्रधानमंत्री प्रचंड ने कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। संयुक्त वार्ता में मोदी ने कहा, 'मुझे याद है 9 साल पहले 2014 में कार्यभार संभालने के तीन महीने के भीतर मैंने नेपाल की पहली यात्रा की थी। उस समय मैंने भारत–नेपाल संबंधों के लिए हिट फार्मूला (हाइवेज, आइवेज एवं ट्रांसवेज) दिया था। मैंने कहा था कि भारत–नेपाल के बीच ऐसे संबंध स्थापित करेंगे कि हमारे बॉर्डर के बेरियर न बने।'' वहीं इस मौके पर नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा मैंने प्रधानमंत्री मोदी को नेपाल आने का निमंत्रण दिया है, मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री शीघ्र ही नेपाल का दौरा करेंगे। इस दौरान दोनों प्रधानमंत्रीयों ने संयुक्त रूप से रेलवे के कुरथा–बीजपूर खंड की ई–योजना का अनावरण किया। साथ ही संयुक्त रूप से बथनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड तक भारतीय रेल कार्गो ट्रेन देने को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्रीयों ने संयुक्त रूप से भारत और नेपाल के मोतीहारी–अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज–2 का शिलान्यास किया। इसके अलावा दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुआ। इसके बाद प्रचंड ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीज डोभाल से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री प्रचंड उज्जैन एवं इंदौर भी गए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. चौधरी,स्वाती रंजन, पूर्वोक्त पृ– 118–12.
2. http://mea.gov.in
3. नवभारत टाइम्स, 17 जुलाई 2015.
4. http://www.pib.gov.in
5. अमर उजाला, 13 अप्रैल 2017.
6. http://mea.gov.in
7. http://mea.gov.in
8. http://www.pib.gov.in
9. http://mea.gov.in
10. दैनिक जागरण, 1 जून 2023.

*****